(ब) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए बिहार राज्य के लिए सतत (1980-81) कीमतों पर तथा अखिल भारत निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद निम्नानुसार है :

(रुपए)

	1990–91	1991–92 (अनन्तिम)	1992–93 (तुरंत अनुमान)
बिहार	1195	1098	1091
अखिल भारत	2213	2167	2216

बिहार में कम प्रति व्यक्ति आय के कारणों का पता लगाने के लिए योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। बिहार सरकार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में कृषि, उद्योग, आधार-संरचना, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास के लिए निवेश तथा गरीबों को सीधे रोजगार तथा आय पैदा करने के लिए कुछ कार्यक्रम शामिल हैं। केन्द्र सरकार भी केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को सहयोग देती है।

National Income spent on Urban Development Schemes

5352. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the total urban population in the country as per the latest census;

(b) the percentage of national income being spent presently on urban development schemes; and

(c) the steps taken to increase the expenditure on urban development schemes keeping in view the urban population?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) (a) As per the 1991 census the total urban population of India is estimated at 217 million.

(b) In 1992-93 the outlay for Urban Development schemes was Rs. 970 crores (State Sector Rs. 855 crores and Central Sector Rs. 115 crores). The estimated National income for the same year was Rs. 622588 crores. Calculations of percentage is not meaningful as National income comprises of both consumption and investment expenditures, both Public and Private.

(c) During the Seventh Five Year Plan, an outlay of Rs. 1,801 crores (Rs. 1,633 crores in the State Sector and Rs. 168

crores in the Central Sector) was provided for Urban Development Schemes. For the 8th Five Year Plan, the total outlay has been raised to Rs. 4,677 crores (Rs. 3,985 crores in the State Sector and Rs. 692 crores in the Central Sector).

Diversion of funds to other schemes

5353. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether instruction have been issued to the State Governments to spend the amount only on those schemes for which the money has been provided in their plan outlays;

(b) if so, whether complaints have been received by Government regarding diversion of these funds to other schemes;

(c) if so, the details thereof for the last two years; and

(d) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (d) In Annual Plan Outlay of States, certain sectoral and sub-sectoral outlay as well as outlays on important schemes and projects are earmarked in consultation with the State Governments who are expected not to deviate from the earmarked outlays. Any deviation from the earmarked outlay have to be got approved by the State Governments from the Planning Commission, justifying such deviation. These proposals are to be sent by 31st December and revised approvals accorded by the Commission having regard to the facts and circumstances of the case. There has been no specific complaint regarding the diversion of funds from one scheme to another.

गुजरात की सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि

5354. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जिले-वार आबंटित की गई है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशी एजेंसियों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान जिले-वार कितनी राशि आबंटित किए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ग) राज्य योजना में केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण तथा ब्लाक अनुदान के रूप में दी जाती है और विशेष समस्या मानदण्ड के तहत निर्धारित राशि को छोड़कर यह किसी परियोजना/कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 170, अनुबंध सं. 106]

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् उपलब्ध कराने के लिए आबंटित निधियां

5355. **श्री रामजी लाल** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आई. आर.ई.पी. के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों